12 मार्च 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

राजव्यवस्था:

1. शीर्ष अदालत ने एसबीआई की याचिका क्यों खारिज की?

सामाजिक न्याय:

1. पश्चिमी घाट की एक जनजाति को समर्थन की आवश्यक है:

अर्थव्यवस्था:

1. "केंद्रीय हस्तांतरण और कुछ राज्यों के हिस्सेदारी के मुद्दे":

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. चीन ने प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर विरोध दर्ज कराया:
2. केंद्र ने चुनाव से पहले CAA नियमों को अधिसूचित किया:
3. MIRV के साथ अग्रि-5 की परीक्षण उड़ान सफल:

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

शीर्ष अदालत ने एसबीआई की याचिका क्यों खारिज की?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

विषय: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।

मुख्य परीक्षा: चुनावी बांड (Electoral Bond)।

पृष्ठभूमि और न्यायालय का निर्णय:

- 11 मार्च को, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड (electoral bonds) का विवरण प्रदान करने की समय सीमा बढ़ाने की एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया, और 12 मार्च की नई समय सीमा तय की।
- एसबीआई को 12 मार्च को कार्य बंद होने तक भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
- अदालत एसबीआई के अध्यक्ष के खिलाफ गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर अवमानना (contempt) याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी, जिसमें खुलासा करने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया गया था।

समय सीमा का विस्तार मांगने के एसबीआई के कारण:

- एसबीआई ने तर्क दिया कि शाखाओं में अस्तव्यस्त एवं बिखरे हुए विवरण प्राप्त करने में समय लगता है।

- दान दाता की गुमनामी बनाए रखने के लिए बांड जारी करने और मोचन से संबंधित जानकारी अलग से संग्रहीत की गई हैं।
- अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 के बीच जारी किए गए 22,217 बांडों का तथ्यात्मक विश्लेषण करने में आंकड़ों के 44,434 सेट का मिलान शामिल था।
- एसबीआई ने योजना के उद्देश्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का हवाला दिया, जिसके लिए भौतिक दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता थी।

विस्तार याचिका को चुनौतियाँ:

- अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि लोकसभा (Lok Sabha) चुनाव से पहले दानदाता की जानकारी को जानबूझकर रोक दिया गया।
- याचिकाकर्ताओं ने डेटा ट्रैसेबिलिटी और एसबीआई के मौजूदा आईटी बुनियादी ढांचे पर विरोधाभासी सरकारी हलफनामों का हवाला दिया।
- उन्होंने तर्क दिया कि एसबीआई के विशाल संसाधन और सरकार को पिछले डेटा प्रस्तुतियाँ दावा की गई कठिनाई का खंडन करती हैं।

न्यायालय की प्रतिक्रिया और टिप्पणियाँ:

- मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) ने एसबीआई के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि फैसले में केवल स्पष्ट प्रकटीकरण की मांग की गई है, न कि जटिल मिलान की।
- न्यायाधीशों ने अदालत के पिछले आदेश के बाद से अपने कार्यों को समझाने में एसबीआई की पारदर्शिता की कमी पर जोर दिया।
- हालाँकि अदालत ने तुरंत अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की, लेकिन अनुपालन न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

विशेषज्ञ राय और विश्लेषण:

- विशेषज्ञों ने डिजिटल पहुंच और सरकार को पिछली त्वरित प्रस्तुतियों का हवाला देते हुए डेटा जटिलता के एसबीआई के दावे की आलोचना की।
- रिपोर्ट में सरकार के साथ एसबीआई के पूर्व सहयोग और 48 घंटों के भीतर डेटा प्रदान करने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।
- ऑडिट ट्रेल्स के लिए बांड पर सीरियल नंबर शामिल करने के लिए एसबीआई के पिछले अनुरोधों ने दाता की जानकारी को ट्रैक करने की इसकी क्षमता को रेखांकित किया है।

सारांश:

- सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड प्रकटीकरण की समय सीमा बढ़ाने की एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। एसबीआई ने डेटा जटिलताओं का हवाला दिया, लेकिन विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं ने इसकी देरी रणनीति की आलोचना की, बैंक की आवश्यक जानकारी तुरंत प्रदान करने की क्षमता पर आरोप लगाया।

पश्चिमी घाट की एक जनजाति को समर्थन की आवश्यक है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

विषय: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन।

मुख्य परीक्षा: वन अधिकार अधिनियम।

विवरण: मकुता गांव और फानी येरावा जनजाति

- कर्नाटक के पश्चिमी घाट (Western Ghats) में स्थित, मकुता गांव मकुता अरण्य वलाया के भीतर फणी येरवा जनजाति का घर है।
- जनजाति ने स्थानीय व्यक्तियों और अधिकारियों की सहायता से वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) के तहत 135 एकड़ वन भूमि पर सफलतापूर्वक जताया है।

आजीविका पैटर्न में बदलाव:

- वन अधिकार प्राप्त करने के बावजूद, समय के साथ जनजाति का वन निर्भरता के प्रति उत्साह कम हो गया है।
- बाजार की अस्थिरता और बिचौलियों द्वारा शोषण के कारण लघु वन उपज को इकट्ठा करना कम आकर्षक हो गया है।
- कई जनजाति के सदस्य अब मजदूरी करना पसंद करते हैं, खासकर कासरगोड, केरल जैसे आसपास के इलाकों में, जहां वे मलयालम बोलने में सहज हैं।

चुनौतियाँ और मुद्दे:

- जनजाति को शराब की लत जैसी एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो किशोरों सहित सभी उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित करती है।
- शराब के दुरुपयोग के कारण स्कूल में उपस्थिति और समग्र सामुदायिक कल्याण में गिरावट आई है।
- समुदाय की अज्ञानता और असुरक्षा के कारण महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और सरकारी अधिकार गैर-आदिवासी सदस्यों को सौंपे जाते हैं।

ध्यान और कार्रवाई का आह्वान:

- गैर सरकारी संगठन, सरकारी अधिकारी और आदिवासी नेता लत जैसे सामाजिक मुद्दों पर नीतिगत ध्यान की कमी पर चिंता व्यक्त करते हैं।
- सरकार से ऐसी चुनौतियों का समाधान करने और हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समुदायों की भलाई को प्राथमिकता देने की अपील की गई है।
- वनवासियों की आजीविका और कल्याण को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए इन सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

सारांश:

- वन अधिकार प्राप्त करने के बावजूद, कर्नाटक के मकुता गांव में फनी येरवा जनजाति को वनों पर निर्भरता कम होने, शराब की लत और नीतिगत ध्यान की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो सरकारी हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

”केंद्रीय हस्तांतरण और कुछ राज्यों के हिस्सेदारी के मुद्दे”:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

विषय: समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: 16वां वित्त आयोग।

विवरण:

- एक वित्त आयोग से दूसरे वित्त आयोग (Finance Commission) तक विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों ने आवंटित संसाधनों की अपनी हिस्सेदारी में लगातार कमी देखी है।
- बारहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों के बीच तुलना करने से पता चलता है कि यह 19.785 प्रतिशत से घटकर 15.800 प्रतिशत हो गया।
- उत्तरी और पूर्वी राज्यों में भी कमी देखी गई, जबकि महाराष्ट्र जैसे पहाड़ी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में वृद्धि देखी गई।

वितरण में मानदंड की भूमिका:

- आय दूरी (income distance) मानदंड जैसे मानदंड व्यक्तिगत राज्यों की कर हस्तांतरण हिस्सेदारी को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं।
- वित्त आयोगों की तुलना में दूरी मानदंड का महत्व कम हो गया है: ग्यारहवें में 62.5% से पंद्रहवें में 45% हो गया है।

- कटौती के बावजूद, दूरी मानदंड महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो उच्चतम आय वाले राज्य के साथ उनकी आय असमानता के आधार पर राज्यों की हिस्सेदारी को प्रभावित करता है।

जनसंख्या मानदंड का प्रभाव:

- जनसंख्या डेटा परिवर्तनों ने कुछ विवादों को जन्म दिया है, विशेष रूप से 1971 से 2011 के डेटा में परिवर्तन के कारण।
- जनसांख्यिकीय परिवर्तन मानदंड की शुरुआत का उद्देश्य बेहतर प्रजनन दर दिखाने वाले राज्यों के लिए दंड को कम करना है।
- कुल मिलाकर, इन परिवर्तनों का संयुक्त प्रभाव सभी राज्यों के लिए मामूली रहा है, जिसमें कुछ तमिलनाडु जैसे राज्य, मामूली सकारात्मक प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं।

समाधान के लिए प्रस्तावित कदम:

- **मानदंड भार को संबोधित करना:**
 - हालांकि आय दूरी का मानदंड उचित वितरण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सोलहवें वित्त आयोग द्वारा इसके महत्व पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
 - 5% से 10% अंकों तक भार में कमी अन्य मानदंडों के खिलाफ इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान हो सकता है।
- **उपकर और अधिभार सीमित करना:**
 - केंद्र द्वारा उपकर और अधिभार में वृद्धि से विभाज्य पूल का आकार कम हो गया है, जिससे राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित हुई है।
 - उपकर और अधिभार पर केंद्र के सकल कर राजस्व का 10% जैसी ऊपरी सीमा निर्धारित करने से राज्यों को लाभान्वित करते हुए एक बड़े विभाज्य पूल को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

● **उचित वितरण बनाए रखना:**

- समायोजन के बावजूद, राज्यों के बीच संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना एक बुनियादी सिद्धांत बना हुआ है।
- विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करते हुए, सभी राज्यों की स्थिरता और विकास के लिए समान वितरण के सार को बनाए रखना आवश्यक है।

सारांश:

- सोलहवें वित्त आयोग को संसाधन हस्तांतरण में राज्य की घटती हिस्सेदारी पर ध्यान देना चाहिए, जो मुख्य रूप से आय दूरी मानदंड से प्रभावित है। प्रस्तावित समाधानों में समान वितरण बनाए रखने के लिए मानदंड भार को संशोधित करना एवं उपकर और अधिभार को सीमित करना शामिल है।

प्रोलिम्स तथ्य:

1. चीन ने प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर विरोध दर्ज कराया:

संदर्भ:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की तीखी अस्वीकृति ने दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव पैदा कर दिया है।
- मोदी ने रणनीतिक सेला सुरंग सहित प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास कनेक्टिविटी और सैन्य तैयारी को मजबूत करना है।

मुद्दा:

- चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा इस प्रधानमंत्री की यात्रा की निंदा में भारत के कार्यो को सीमा मुद्दे को जटिल बनाने और क्षेत्रीय स्थिरता को बाधित करने वाला बताया गया।

- चीन ने इस क्षेत्र पर संप्रभुता के भारत के दृढ़ दावे के बावजूद, अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीनी भाषा में "ज़ंगनान" कहा जाता है, पर अपना दावा दोहराया है।
- प्रधानमंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे के विरोध में तीखी अस्वीकृति ने नवीनतम वैचारिक आदान-प्रदान ने मौजूदा तनाव को बढ़ा दिया है, विशेष रूप से वर्ष 2020 में शुरू हुए सीमा गतिरोध के बाद से।
- भारत मौजूदा तनाव के बीच अपनी सीमाओं की रक्षा करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए दृढ़ है।

महत्व:

- जैसा कि राजनयिक संवाद जारी है, यह विवाद व्यापक क्षेत्रीय जटिलताओं और दो एशियाई दिग्गजों के बीच क्षेत्रीय असहमति के प्रबंधन की चुनौतियों को रेखांकित करता है।

2. केंद्र ने चुनाव से पहले CAA नियमों को अधिसूचित किया:

संदर्भ:

- लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की नागरिकता संशोधन नियम, 2024 की हालिया अधिसूचना, 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम ([Citizenship Amendment Act \(CAA\)](#)) के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत देती है।

सम्बन्धित जानकारी:

- CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अनिर्दिष्ट व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना है।

- नए शुरू किए गए नियमों के तहत, आवेदकों को छह प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और उल्लिखित देशों में संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, उन्हें भारत में अपने "प्रवेश की तारीख" निर्दिष्ट करनी होगी, जैसा कि नियमों में कहा गया है।
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और एक अधिकार प्राप्त समिति, जिसमें खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न अधिकारी शामिल होंगे, जिला स्तर पर जांच प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
- एक निर्दिष्ट पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की शुरूआत आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, जिससे कुशल दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं की सुविधा मिलती है।

महत्व:

- नागरिकता संशोधन नियम, 2024 की अधिसूचना, भारत की नागरिकता नीतियों में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती है, जो सताए गए अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

3. MIRV के साथ अग्नि-5 की परीक्षण उड़ान सफल:**संदर्भ:**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीन्ट्री व्हीकल (एमआईआरवी) तकनीक से लैस अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर की शुरुआत की।

सम्बन्धित जानकारी:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक से लैस अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा मिशन दिव्यास्त्र के तहत आयोजित यह परीक्षण देश के लिए एक बड़ी तकनीकी सफलता है।
- 'मिशन दिव्यास्त्र' नामक यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया।
- एमआईआरवी तकनीक एक ही मिसाइल को कई हथियार तैनात करने की अनुमति देती है, जिससे एक साथ कई स्थानों को निशाना बनाकर इसकी रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ जाती है।
- एमआईआरवी तकनीक एक ही मिसाइल को कई हथियार तैनात करने की अनुमति देती है, जिससे एक साथ कई स्थानों को निशाना बनाकर इसकी रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ जाती है।
- प्रधान मंत्री मोदी ने डीआरडीओ वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की, एमआईआरवी क्षमताओं के साथ अग्नि -5 मिसाइल के स्वदेशी विकास पर प्रकाश डाला, एमआईआरवी क्षमता रखने वाले देशों की लीग में भारत के प्रवेश को रेखांकित किया।

महत्व:

- सफल मिशन ने स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर पैकेजों के माध्यम से रक्षा प्रणालियों में भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति की पुष्टि की, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।
- परियोजना निदेशक सहित महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान ने भारत के वैज्ञानिक समुदाय की समावेशी और विविध प्रकृति को रेखांकित किया।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. न्यायालय की अवमानना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का संविधान भारत में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित और विनियमित करता है।
2. अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना अवमानना के तहत सजा का आधार है।
3. अदालती मामले की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग को कभी भी अवमानना नहीं माना जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: b

प्रश्न 2. भारत में MIRV तकनीक वाली अग्नि-5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अग्नि-5 एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है।
2. एमआईआरवी (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली-टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल) तकनीक एक अग्नि-5 मिसाइल को अलग-अलग लक्ष्यों पर कई परमाणु हथियार पहुंचाने की अनुमति देती है।
3. अग्नि-5 एमआईआरवी का विकास भारत की निवारक क्षमताओं को मजबूत करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

प्रश्न 3. भारत में वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है।
2. वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है।
3. वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

प्रश्न 4. पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पश्चिमी घाट दुनिया के जैव विविधता के हॉटस्पॉट में से एक हैं, जो अपने सदाबहार जंगलों के लिए जाने जाते हैं।
2. पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को कवर करता है।
3. नीलगिरि पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

प्रश्न 5. भारतीय इतिहास में 8 अगस्त, 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (a) भारत छोड़ो प्रस्ताव एआईसीसी (AICC) द्वारा अपनाया गया था।
- (b) अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया।
- (c) सात प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया।
- (d) द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्रिप्स ने पूर्ण डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा।

उत्तर: a

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. वित्त आयोगों द्वारा लगातार भारतीय राज्यों के बीच धन के क्षैतिज हस्तांतरण की योजना उनमें से कुछ में प्रतिशोध का कारण क्यों बन रही है? (10 अंक, 150 शब्द) [जीएस-3, अर्थव्यवस्था] (Why has the scheme of horizontal devolution of funds among the Indian states by successive Finance Commissions causing retaliation in some of them? (10 marks, 150 words) [GS-3, Economy])

प्रश्न 2. जनजातीय कल्याण में सरकार द्वारा कौशल उन्नयन और रोजगार सृजन के उपायों से कहीं अधिक शामिल है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) [जीएस-2, सामाजिक न्याय] (Tribal welfare encompasses more than upskilling and employment generation measures by the Government. Critically evaluate. (15 marks, 250 words) [GS-2, Social Justices])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)